CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

हिमाचल प्रदेश सरकार "हिम-गंगा" योजना शुरू करने जा रही है

हिमाचल प्रदेश सरकार "हिम-गंगा" योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करना है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पशुपालकों से दूध एकत्र करना और दूध के उप-उत्पादों को बेचना है।

"हिम-गंगा" योजना के तहत पशुपालकों को वास्तविक लागत के आधार पर उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त होगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन प्रणालियों की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

सरकार दुग्ध उत्पादकों को क्षेत्रीय और मौसमी कीमतों में उतार-चढ़ाव से भी बचाएगी, खासकर समाज के गरीब तबकों से। रुपये का आवंटन। "हिम-गंगा" योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और इसे धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने से पहले किसानों को जोड़कर पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा।

इस बीच, सीएम सुक्खू ने कहा कि दुग्ध किसानों की आय बढ़ाने के लिए, इन सहकारी समितियों के माध्यम से दूध और उसके उत्पादों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करते हुए, आवश्यकतानुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।

FSSAI दूध, डेयरी उत्पादों के लिए मिलावट विरोधी अभियान चलाएगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) मिलावट पर अंकुश लगाने के अपने चल रहे प्रयास में दूध और डेयरी उत्पादों की राष्ट्रव्यापी जांच करेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है लेकिन रसायनों और अन्य पदार्थों में मिलावट एक समस्या बनी हुई है क्योंकि बढ़ती आय से मांग बढ़ जाती है। खाद्य सुरक्षा निकाय देश भर के जिलों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर नमूने एकत्र करेगा।

FSSAI ने एक विज्ञप्ति में कहा, "दूध को चुनने के पीछे तर्क हमारी खाद्य संस्कृति में या तो एक ताजा तरल पदार्थ या प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों के रूप में इसकी अपरिहार्य भूमिका के कारण है।"

प्रयास के तहत खोया, छेना, पनीर, घी, मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसे उत्पादों के नमूनों की भी जांच की जाएगी। यह मिलावट रोधी अभ्यास गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए नमूनों की जांच करेगा। यह मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों के हॉटस्पॉट की भी पहचान करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

जे चिनचुरानी ने कहा 'टिकाऊ डेयरी' के लिए सही कदम उठाए जाने चाहिए

पशुपालन मंत्री जे. चिनचुरानी ने कहा, 'टिकाऊ डेयरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गायों में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर उपाय अपनाए जाएंगे,' विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में राज्य कृषि प्रबंधन में केरल पशुधन विकास बोर्ड (केएलडीबी) के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वाराआयोजित 'सतत डेयरी के लिए उत्पादकता का अनुकूलन' पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र का उद्घाटन किया |

राज्य में उच्च फ़ीड और रखरखाव लागत, बीमारियों और दूध उत्पादन में वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। प्रजनन और प्रजनन प्रबंधन, लागत प्रभावी पोषण, मूल्यवर्धन और लाभदायक विपणन रणनीतियों पर भी चर्चा की गई।

आदरणीय चिनचुरानी ने औपचारिक रूप से KLDB की जीनोमिक लैब द्वारा प्राप्त NABL मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया।

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की घोषणा की

भारत सरकार ने भारत पशुधन-राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) के कार्यान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से जम्मू और कश्मीर का चयन किया है।

एनडीएलएम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम/पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वभौमिक फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) टीकाकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी गोजातीय और छोटे जुगाली करने वालों के लिए एक अद्वितीय 12-अंकीय बारकोडेड टैग आईडी का लाभ उठाएगा।

इस मिशन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक किसान-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में एक डिजिटल पशुधन डेटाबेस की स्थापना, बेहतर किसान सेवाएं और समय पर सूचना अद्यतन शामिल होंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में, मौजूदा आईएनएपीएच प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत, एक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए, पशु/भेड़पालन के संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा नामित जिला नोडल अधिकारी एनडीएलएम प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये अधिकारी बाद में केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सभी INAPH उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे, जिससे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उनकी तैयारी की गारंटी होगी। डेटा को एकीकृत करने से जम्मू और कश्मीर में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म को प्राप्त करने पर केंद्रित प्रजनन कार्यक्रम के निर्माण में मदद मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश में गांठदार वायरस का खतरा मंडरा रहा है

पशुपालन विभाग ने ऊना और हमीरपुर जिलों में गाय-भैंसों में पाए जाने वाले गांठदार वायरस के खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. पड़ोसी राज्यों पंजाब और उत्तराखंड में वायरस के फैलने की खबरों के बाद अधिकारियों ने दोनों जिलों को अलर्ट कर दिया है।

पिछले साल हमीरपुर और ऊना जिले में लगभग 25,000 जानवर गांठ वाले वायरस से प्रभावित हुए थे, अकेले ऊना में लगभग 1,209 जानवर मर गए थे।

उन्होंने पशुपालकों से भी अपील की कि वे अपने मवेशियों में तेज बुखार, भूख न लगना, दूध की कमी और त्वचा में मोटी गांठ जैसे किसी भी लक्षण की सूचना तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय या फार्मेसी को दें। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में इस साल अब तक इस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

पशुपालन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऊना जिले में पशुपालन विभाग ने इस बीमारी के खिलाफ कमर कस ली है. विभाग ने डेयरी किसानों से अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की है और पड़ोसी राज्यों से पशुओं की खरीद-बिक्री नहीं करने को कहा है|

ऊना के पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. जय सिंह सेन ने बताया कि जिले के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों में वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है| सेन ने जोर देकर कहा, "गांठ प्रभावित क्षेत्रों से पशुओं की खरीद-बिक्री न करें।"

पशुपालन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऊना जिले में पशुपालन विभाग ने इस बीमारी के खिलाफ कमर कस ली है. विभाग ने डेयरी किसानों से अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की है और पड़ोसी राज्यों से पशुओं की खरीद-बिक्री नहीं करने को कहा है|

कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ पशु आधार के तहत 2.5 लाख मवेशियों को नामांकित करने के लिए तैयार है

पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग पशु आधार पंजीकरण के तहत दक्षिण कन्नड़ जिले में 2.5 लाख से अधिक मवेशियों को नामांकित करने के लिए कमर कस रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क (INAPH) के तहत बायोमेट्रिक विवरण के रूप में जिले के प्रत्येक घरेलू मवेशी को थूथन पैटर्न के साथ विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी।

इससे पहले, मवेशियों को 12 अंकों की पहचान संख्या वाले ईयर टैग दिए जाते थे। इससे जानवरों में कान पर चोट, संक्रमण और एलर्जी हो रही है। कानों में टैग लगने से गायों के घायल होने के उदाहरण सामने आए हैं|

पौधों और बाड़ों के लिए। कान के टैग को बदलने के लिए सरकार ने सभी घरेलू मवेशियों के लिए थूथन पैटर्न पहचान शुरू करने का फैसला किया है। थूज़ल पैटर्न को एक रीडर का उपयोग करके स्कैन किया जाएगा और इसे विशिष्ट पहचान के निर्माण के उद्देश्य से बायोमेट्रिक डेटा के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक मवेशी का अपना अनूठा थूथन पैटर्न होता है, जो बाकी जानवरों से अलग होगा।' कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (ई-गवर्नेंस) इस उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर और ऐप उपलब्ध कराएगा।

"20वें मवेशी जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले में मवेशी हैं, जिनमें 65,997 स्वदेशी और 1,84,572 क्रॉसब्री शामिल हैं।
डेटा विभाग को जिले में मवेशियों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने में मदद करेगा, विशेष रूप से बीमारियों से निपटने के लिए। पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के उप निदेशक डॉ अरुण कुमार शेट्टी ने कहा कि विभाग जिले में 2.5 लाख से अधिक घरेलू मवेशियों के थूथन पैटर्न एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

एनडीडीबी सहायक उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख महिला डेयरी किसानों के साथ साझेदारी करेगी।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य सरकार की महिला सामर्थ्य योजना (एमएसवाई) के तहत तीन महिला स्वामित्व वाली दुग्ध उत्पादक कंपनियों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। इस पहल के साथ, सरकार का लक्ष्य यूपी के 17 जिलों के 2,800 से अधिक गांवों के लगभग 1.50 लाख ग्रामीण महिला डेयरी किसानों को शामिल करना है। जानकारी के अनुसार, जब तक यह पहल अपने पांचवें वर्ष में है, तब तक इसका उद्देश्य प्रति दिन 7 लाख लीटर से अधिक दूध की खरीद करना है।

सामर्थ्य, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा और श्रीजनी के नाम से इन दुग्ध उत्पादक कंपनियों का मुख्यालय क्रमशः रायबरेली, गोरखपुर और बरेली में होगा। एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने बताया कि देश में दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में अभी भी एक बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है। "महिला डेयरी किसानों को एक साथ लाने की यह पहल न केवल उन्हें बाजार तक पहुंच और आजीविका प्रदान करेगी बल्कि उनकी उद्यमशीलता की क्षमता को भी उजागर करेगी।"

महिला डेयरी किसानों को शामिल करने की घोषणा के बाद से, राज्य सरकार ने तीन कंपनियों की स्थापना के लिए एक परिव्यय तैयार किया है, और उन्हें जितनी जल्दी हो सके चलाने के लिए काम शुरू हो चुका है, यूपी राज्य के राज्य मिशन निदेशक सी इंदुमती ने कहा ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका MSY एक हिस्सा है।

मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट सुपरवाइजर जॉब रोल में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के फील्ड स्टाफ ने CEDSI द्वारा आयोजित एक अपस्किलिंग प्रोग्राम में भाग लिया

डेयरी उद्योग के भीतर पेशेवरों की दक्षता बढ़ाने के एक ठोस प्रयास में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के सम्मानित फील्ड स्टाफ के लिए एक व्यापक 3-दिवसीय अपस्किलिंग कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक की विशेष भूमिकाओं में लक्षित प्रशिक्षण देने के लिए था। यह कार्यक्रम एक जबर्दस्त सफलता साबित हुआ, क्योंकि प्रतिभागियों को उन्नत ज्ञान और कौशल के साथ सुसज्जित किया गया था, जो दूध खरीद प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और इनपुट आपूर्ति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए अनिवार्य था। 19 से 21 मई 2023 तक, यह कार्यक्रम औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, जहाँ लगभग 40 फील्ड स्टाफ को सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया था।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया